www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 5 अक्टूबर 2019

दैनिक जागरण

जो चीजें कष्ट पहुंचाती हैं, वही सिखाती हैं

एक और बैंक घोटाला

पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक में गड़बड़ी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया जाना यही बताता है कि एक और बैंक घोटाले की चपेट में आ गया। यह ठीक नहीं कि सरकारी बैंकों के कामकाज के बाद सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली भी संदेह के दायरे में आ गई। इसका सीधा मतलब है कि बैंकों का नियमन और उनके कामकाज की निगरानी सही तरह नहीं हो रही है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के बर्खास्त प्रबंध निदेशक ने यह मान लिया कि निदेशक मंडल ने एनपीए की वास्तविक स्थिति छिपाई। सवाल है कि जब निदेशक मंडल के सदस्य हेराफेरी कर रहे थे तो वह स्वयं क्या कर रहे थे? उनकी मानें तो ऑडिट करने वालों ने भी अपना काम सही तरह नहीं किया। पता नहीं सच क्या है, लेकिन ऑडिट के नाम पर खानापूरी का यह पहला मामला नहीं। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की ओर से कुछ ऐसी कंपनियों और खासकर एचडीआइएल नामक कंपनी को जरूरत से ज्यादा कर्ज दे दिया गया। वह कर्ज लौटाने की स्थिति में ही नहीं थी। यह भी हो सकता है कि उसका कर्ज लौटाने का इरादा ही न हो। भले ही इस कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन बात तो तब बनेगी जब इस बैंक को ठगने और लाखों बैंक उपभोक्ताओं के भरोसे का खून करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

निःसंदेह सख्त कार्रवाई की जद में वे भी आने चाहिए जिनके दखल से अपात्र लोगों को भारी-भरकम कर्ज दिया गया। यह दखल राजनीतिक लोगों का ही रहा होगा, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि सहकारी बैंक नेताओं या फिर उनके सगे-संबंधियों की मनमानी का अड्डा बन गए हैं। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र सहकारी बैंक में वह घोटाला है जिसमें शरद पवार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यह ठीक है कि रिजर्व बैंक अब सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह ख्याल एक और घोटाला सामने आने के बाद ही क्यों आया? इस सवाल से सरकार को भी दो-चार होना होगा, क्योंकि वह इससे अनजान नहीं हो सकती कि सहकारी बैंक दोहरे नियमन से गुजर रहे हैं। ये बैंक रिजर्व बैंक के दायरे में तो हैं, लेकिन उन पर वास्तविक नियंत्रण सहकारी समितियों का होता है। इन समितियों पर आम तौर पर नेताओं का कब्जा होता है और वे सहकारी बैंक चलाने के नाम पर बंदरबाट ही अधिक करते हैं। कम से कम अब तो ऐसे कदम उठाए ही जाने चाहिए जिससे हर तरह के बैंक घपलेबाजी से बचे रह सकें।

दुर्गापूजा के रंग

दुर्गापूजा के लिए यूं ही बंगाल और खासकर कोलकाता विश्वभर में मशहूर नहीं है। क्योंकि आयोजन में साल भर की मशक्कत, तैयारी एवं सोच साफ झलकती है। जितने पंडाल उसके उतने ही रंग और उसने ही संदेश। वैसे तो बंगाल में थीम आधारित दुर्गापूजा का चलन कई वर्ष पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब समस्याओं से लेकर उपलब्धियों तक को पूजा पंडाल एवं दुर्गा प्रतिमा के जरिए लोगों के सामने परोस दिया जाता है। कोलकाता के दुर्गापूजा पंडाल समसामयिक विषयों पर आधारित रहे हैं। परंतु कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक रंग भी चढ़ ही जाता है। एक ओर जहां बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर पंडाल बनाए गए हैं तो दूसरी ग्लोबल वार्मिंग का संदेश देता भी पंडाल है। वहीं एक पंडाल ऐसा बना है जिसने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और शरणार्थियों की परेशानी को उकेरा है। तृणमूल नेता द्वारा संचालित इस पूजा समिति ने इस साल एनआरसी को पूजा थीम बनाया है। कसबा के राजडांगा में पंडाल बैडमिंटन रैकेट और शटलकॉक से तैयार किया गया है। पूजा समिति का कहना है कि बैडमिंटन और शटलकॉक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शरणार्थी और कुछ नहीं, बल्कि शटलकॉक हैं, जिन्हें दो देश एक-दूसरे की तरफ फेंकते हैं। यही नहीं पंडाल में दो देश की सीमाओं को दर्शाने के लिए लोहे के तार भी लगाए गए हैं, जो देशों को भौगोलिक रूप से बांटते हैं। पंडाल को तैयार करने वाले कलाकार का कहना है कि एक चिड़िया का विशालकाय मॉडल भी बनाया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि लोग सीमाओं में बंधे हैं और विभाजन के बाद शरणार्थी बन जाते हैं, लेकिन अन्य प्राणियों के साथ ऐसा नहीं है। वे मनुष्य की तुलना में अधिक आजाद हैं। इस पूजा समिति ने जुलाई से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आयोजकों से यह पूछे जाने पर कि पूजा पंडाल में शरणार्थियों को थीम बनाने पर क्या विवाद पैदा होगा तो इस पर कहा, 'हमारी थीम शरणार्थियों की रक्षा के बारे में है और अगर आप विस्थापित लोगों के मुद्दे पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से एनआरसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।' पिछले साल दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर में एक पूजा समिति ने एनआरसी पर एकदम अलग ढंग से प्रभावित लोगों की परेशानियां दिखाई थीं। शहर के बड़ाबाजार क्षेत्र में बालाकोट हवाई हमले को जीवंत करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए पंडाल में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों, लड़ाकू विमान और मृत आतंकवादियों के प्रतिरूप लगाए गए हैं।

राहुल-प्रियंका को सीख देते आदित्य ठाकरे

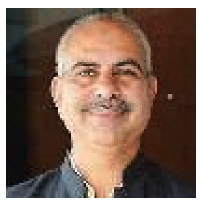

रशीद किदवई

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के विपरीत 29 साल के आदित्य ठाकरे अपने लक्ष्य को लेकर बहुत साफ नजर आते हैं

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का चुनाव मैदान में उतरना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी घटना है। आदित्य ठाकरे का चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजनीति का पाठ पढ़ाने और साथ ही राह दिखाने वाला है। एक समय था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी से अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का बार-बार आग्रह किया, लेकिन राहुल ने उनका प्रस्ताव नकार दिया। दरअसल राहुल गांधी के चाटुकारनुमा सलाहकारों ने यह तर्क दिया कि गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते उन्हें केवल प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। राहुल गांधी यह समझ नहीं पाए कि देश और समाज, विशेषकर युवाओं का मिजाज बदल चुका है और राजनीति में केवल उन लोगों की पूछ-परख होगी जिनके पास सार्वजनिक जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां होंगी। राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी वाड्रा भी आम जनता और कांग्रेसजनों की भावनाएं समझ नहीं पा रहीं हैं। यदि वह वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव हार भी जातीं तो भी एक लड़ाका के तौर पर सामने आतीं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इन्कार करके खुद को रण छोड़ने वाला नेता ही साबित किया। अगर उन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं था तो फिर उनकी ओर से ऐसी संभावना नहीं उभारी जानी चाहिए थी।

लोकसभा चुनाव के बाद से प्रियंका उत्तर प्रदेश की रट लगाए जा रही हैं, लेकिन प्रदेश में उनकी सक्रियता केवल गाहे-बगाहे ही नजर आती है। न तो प्रियंका का दिल्ली से मोह छूट रहा है और न ही उनकी राजनीतिक गतिविधियां सोशल मीडिया से आगे जा पा रही हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के विपरीत आदित्य ठाकरे अपने लक्ष्य को लेकर बहुत साफ हैं। खांटी विचारधारा यानी कोर आइडियोलॉजी को लेकर शिवसेना के मन में कोई संशय नहीं है। आर्थिक मामलों और खासकर रोजगार के साथ-साथ सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं की कमी को लेकर सेना केंद्र की भाजपा सरकार को बिल्कुल नहीं बख्शती। उसका अपना आकलन है कि एक राज्य स्तर की पार्टी होने के नाते उसका अस्तित्व इन मुद्दों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की स्थिति भिन्न है। कांग्रेस में विचारधारा के नाम पर 2014 से अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। संगठन की कमजोरी के चलते बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल या तो कांग्रेस को मुंह लगाने को तैयार नहीं हैं या फिर कुछ सीटों का लालच दे कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी की किरकिरी होती जा रही है। पिछले कुछ महीनों से आदित्य ठाकरे ने अपनी और साथ ही अपनी पार्टी की छवि बदलने का प्रयास किया है। चाहे समुद्र किनारे गंदगी साफ करने का का मामला हो या लोकल बस और ट्रेन में सफर करने का या फिर प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम छेड़ने का, आदित्य ठाकरे जमीनी स्तर पर जनता और उससे जुड़े मुद्दों के साथ खड़े नजर आते हैं।

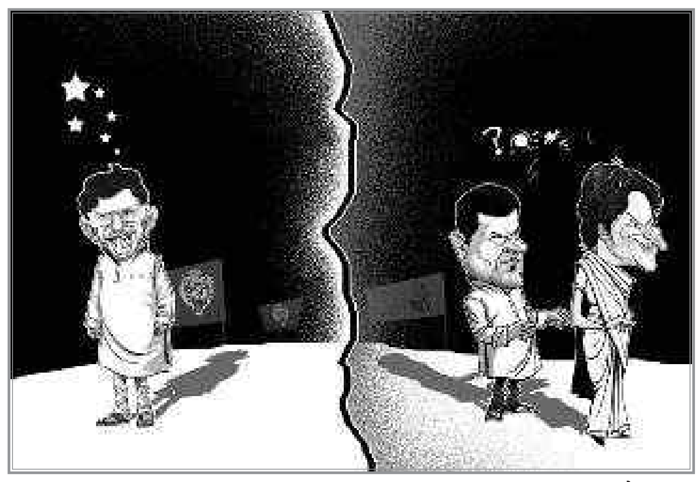

अवधेश राजपूत

यह सही है कि ठाकरे परिवार हर लिहाज से नेहरू-गांधी परिवार से भिन्न है, लेकिन एक समानता जरूर है कि दोनों परिवारों के राजनीतिक सदस्यों को वोट और सियासत पर पकड़ को लेकर एक गुमान था। वह अपने आप को सर्वप्रिय और सबसे ऊपर समझते आ रहे थे। 2014 और उसके बाद की राजनीति ने उनके कस-बल ढीले कर दिए, लेकिन शायद ऐंठन है कि जाती नहीं। जो भी हो, यह कहा जा सकता है कि आदित्य ठाकरे को यह समझ आ गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में भाजपा नेताओं को मातोश्री में बार-बार तलब नहीं किया जा सकता और न ही बड़बोले बयानों या मुखपत्र की बेलगाम संपादकीय टिप्पणियों से जनसमर्थन जुटाया जा सकता है। वैसे आदित्य ठाकरे का चुनाव लड़ने का फैसला चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भाजपा का महाराष्ट्र में जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पराक्रम पर भाजपा अस्सी फीसद सीटों पर जीतने की क्षमता रखती है। इसी कारण भाजपा की पुरानी और विश्वसनीय सहयोगी शिवसेना अपनी कामयाबी को लेकर इतनी आश्वस्त नहीं है। यदि 24 अक्टूबर को यानी नतीजे वाले दिन शिवसेना भाजपा के मुकाबले में नजर नहीं आती तो यह आदित्य ठाकरे की विफलता को दर्शाएगा। आदित्य ठाकरे का चुनावी मैदान में उतरना तभी सार्थक सिद्ध होगा जब शिवसेना की कामयाबी भाजपा से बेहतर या फिर बराबर हो। 29 साल के आदित्य ठाकरे शायद यह बखूबी समझ गए हैं कि शिवसेना पचास सीट जीत कर न तो भाजपा की बराबरी कर पाएगी और न ही अपने महत्वाकांक्षी लोगों को शिवसेना से भाजपा में जाने से रोक पाएगी। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब बड़ी और चुनावी दृष्टि से कामयाब पार्टी ने अपनी सहयोगी अथवा मित्र पार्टी पर कब्जा जमा लिया। देखना है कि महाराष्ट्र में क्या होता है? साफ है कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर है। शिवसेना को भाजपा से लगातार खतरा महसूस हो रहा है और उसका विचारधारा पर आधारित विश्वास डगमगा गया है, लेकिन दोनों अलग होने को तैयार नहीं हैं। भाजपा के आकलन में मित्रवत शिवसेना विपक्षी सेना के मुकाबले सस्ता सौदा है। शिवसेना भी अपने बनाए हुए इस भ्रम से प्रसन्न है कि महाराष्ट्र में उसके बगैर भाजपा का काम नहीं चल सकता, लेकिन चुनाव के बाद यह स्थिति बदल सकती है। शक्तिशाली भाजपा महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहेगी। इस हालत में उसका शिवसेना से सीधा और निर्णायक टकराव हो सकता है। क्या आदित्य ठाकरे इस स्थिति के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब भविष्य ही देगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आदित्य ठाकरे का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उतरना एक साहसी, किंतु जोखिम भरा कदम है। यह शिवसेना के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

यदि महाराष्ट्र में एक बार फिर देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन जाती है और आदित्य ठाकरे उपमुख्यमंत्री बनने में सफल रहते हैं तो इससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। इससे बहुत सी चीजों के साथ यह भी पता चलेगा कि राजनीति में आत्मविश्वास के साथ-साथ यथार्थ का धरातल अति महत्वपूर्ण होता है। कामयाबी के लिए केवल किसी नाम के सहारे या पुराने ढर्रे पर राजनीति करना काफी नहीं है। विवेक और कौशल ही राजनीति में कामयाबी और नाकामयाबी को परिभाषित करते हैं। महाराष्ट्र के नतीजे कुछ भी हों, 29 साल के आदित्य ठाकरे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सीख लेने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और ओआरएफ के विजिटिंग फैलो हैं)
response@jagran.com

मजबूत आधारशिला पर योगी सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना आधा कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं। वैसे तो ढाई-वर्ष का कार्यकाल किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए कम है, फिर भी जनता को जानने में रुचि होगी कि योगी आदित्यनाथ का वर्तमान राजनीतिक योग क्या संकेत दे रहा है? इसके लिए योगी सरकार के काम-काज पर दृष्टि डालना होगी। किसी भी सरकार के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? प्रत्येक सरकार अपनी उपलब्धियों का बढ़-चढ़ कर गुणगान करती है, लेकिन कई बार ऐसी सरकारों को जनता चुनावों में हटा देती है। उत्तर प्रदेश इसका ज्वलंत उदाहरण है। 2007 में मायावती के नेतृत्व में बहुमत की बसपा सरकार को जनता ने 2012 में हटा दिया और सपा के अखिलेश यादव को कमान सौंपी। 2017 में जनता ने अखिलेश को हटा दिया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। क्या योगी इस सिलसिले को रोक सकेंगे? सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी सरकारों के बारे में बढ़चढ़ कर बखान किया, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि क्या वे जनता की समस्याओं का समाधान कर पाए? समस्याओं के समाधान हेतु सरकारें प्रायः नियंत्रणकारी रुख अपना लेती हैं। योगी ने भी शुरू में एंटी-रोमियो स्क्वॉड, अवैध बूचड़खानों एवं खनन पर प्रतिबंध, अपराधियों के एनकाउंटर आदि निर्णय लेकर 'नियंत्रणकारी' सरकार होने का संदेश दिया, लेकिन धीरे-धीरे वह इस दायरे से बाहर निकले और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करने लगे। निःसंदेह योगी की छवि कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री की है पर मुख्यमंत्री की छवि सरकार के मूल्यांकन का आधार नहीं हो सकती।

उत्तर प्रदेश सरकार को दक्षता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता के मानक पर ही आंका जाएगा। योगी सरकार को देखना होगा कि क्या उसने जनता से किए वायदे पूरा करने और स्वयं अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी दिखाई है? सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया 73 हजार करोड़ रुपये के भुगतान और किसानों की कर्ज-माफी लक्ष्य को पूरा करने का दावा किया, लेकिन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार 2 सितंबर 2019 तक गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 6480 करोड़ रुपये अभी भी शेष है। योगी सरकार ने 2018-19 में राजस्व में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। उज्ज्वला, पीएम किसान सम्मान, स्वच्छ भारत और पीएम आवास योजना में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य

डॉ. एके वर्मा

हर सरकार की तरह उप्र सरकार को भी दक्षता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता के मानक पर ही आंका जाएगा

बन कर उभरा है, पर प्रदेश में विकास के साथ-साथ शांति-व्यवस्था और महिला-सुरक्षा के प्रश्न जटिल हैं। राजनीतिक विद्वेष के अलावा अनेक सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक कारक भी अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। सभी पार्टियां सत्तारूढ़ होने पर इन समस्याओं से जूझती हैं, लेकिन जब अपराध या दुष्कर्म की कोई घटना होती है तो उससे मिल कर लड़ने की बजाय वे आपस में ही लड़ने लगती हैं। यह समस्या सारे देश में है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद विश्व का पांचवां बड़ा देश है। चूंकि यहां की समस्याएं, विविधताएं, जटिलताएं असंख्य हैं इसलिए योगी सरकार इन समस्याओं से केवल सतत लड़ने का संकल्प ही अपना उद्देश्य रख सकती है। इस दृष्टि से प्रदेश में योगी-शासन में सांप्रदायिक दंगे न होना सराहनीय है। कुंभ और लोकसभा चुनाव जैसे बड़े कार्यक्रम भी शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। प्रदेश में जातिवादी राजनीति का अनेक वर्षों से बोलबाला रहा, लेकिन जबसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने सबका साथ-सबका विकास को धार दी तबसे उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव हुआ है।

जबसे भाजपा को सभी वर्गों-जातियों का समर्थन मिला है, उसकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। दलितों, अन्य-पिछड़ा-वर्ग और मुस्लिम समुदाय से भाजपा के नए समर्थकों की मानसिकता सरकार से ज्यादा लाभ प्राप्त करने की है। मोदी सरकार का अनुसरण कर योगी सरकार ने भी सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू कराने का प्रयास किया है, लेकिन जिस प्रशासनिक मशीनरी द्वारा योजनाओं को लागू किया जाता है वह भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पा रही है। परिणामस्वरूप चाहे मनरेगा हो, बेटी-बचाओ बेटी-पढ़ाओ अभियान हो, शौचालय-निर्माण हो या अन्य उनमें ग्राम-प्रधान, पंचायत अधिकारी और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से योजनाओं को लागू करने में भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। इसका एक कारण यह भी है कि जो लोग विधायक-मंत्री बने हैं उनकी मानसिकता चुनाव में खर्च धन को अर्जित करने और अगला चुनाव जीतने के लिए धन-संग्रह करने की है। भ्रष्टाचार का कोई त्वरित इलाज नहीं। हालांकि केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार ने भी भ्रष्ट और नाकारा दो सौ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया और 417 अधिकारियों को निलंबित किया या उनकी सर्विस-बुक में प्रतिकूल प्रविष्टि की। एक नई पहल करते हुए योगी ने अपने मंत्रियों और सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ में सुशासन, प्रबंधन, नेतृत्व और जनसहभागिता का पाठ पढ़ा।

यह इंगित करता है कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार की दक्षता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता बढ़ाने को लेकर सचेष्ट हैं। योगी सरकार से जनता के सभी वर्गों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, पर बार-बार के चुनाव योगी का ध्यान शासन से भटकाते हैं। अक्टूबर में कई सीटों के विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। वैसे हमीरपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का नतीजा योगी सरकार को बल देने वाला है। अपनी हिंदुवादी छवि के बावजूद योगी ने अभी तक शासन में निष्पक्षता दिखाई है और सांप्रदायिक-सौहार्द एवं सामाजिक-सद्भाव बनाए रखा है। यह एक ऐसी मजबूत आधारशिला है जिस पर युवा-रोजगार, उद्यमिता, महिला-सुरक्षा, सशक्तीकरण, किसानों एवं गरीबों की आय में वृद्धि और संगठित-असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक-सुरक्षा देने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता से कठोर निर्णय लेने में आसानी रहेगी, लेकिन इसके लिए नौकरशाही, पुलिस और जन-प्रतिनिधियों की मानसिकता और कार्य-शैली पर तत्काल ध्यान देना होगा।

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

भावना

अगर किसी इंसान के अंदर कोई भावना ही नहीं है तो आप उसे इंसान नहीं कह सकते। जो लोग कहते हैं कि भावनाएं आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते में बाधक हैं, वे अगली बात यह बताएंगे कि आपका दिमाग और शरीर भी एक बाधा हैं। एक तरह से देखें तो यह सच है। आपका शरीर, दिमाग, भावनाएं और ऊर्जा ये तमाम चीजें या तो आपके जीवन में बाधा बन सकती हैं या फिर यही चीजें जीवन में आगे बढ़ने का सोपान भी बन सकती हैं। यह सब इस बात पर निर्भर है कि आप उनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं।

आपकी भावनाएं आपके दिमाग में चल रहे विचारों से अलग नहीं होतीं। जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप महसूस करते हैं। विचार शुष्क होते हैं और भावनाएं रसीली। आपको लगता है कि आपका दिमाग भी एक समस्या है। नहीं, समस्या दिमाग नहीं है। समस्या यह है कि आपको यह नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। इसे ऐसे समझ सकते हैं। आप गाड़ी चलाना नहीं जानते और हमने आपको तेजी से चलने वाली एक कार दे दी। अब यह कार न सिर्फ आपकी जिंदगी के लिए एक समस्या हो गई, बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए भी, क्योंकि आप कार चलाना नहीं जानते। जाहिर है, समस्या की वजह मशीन नहीं है, बल्कि आपका दिमाग है, क्योंकि आपने इसे संभालने का तरीका सीखने की कोई कोशिश नहीं की।

दिमाग और भावनाएं समस्या नहीं हैं। भावनाएं तो मानवीय जीवन का एक खूबसूरत पहलू हैं। अगर भावनाएं न हों तो लोग बदसूरत हो जाएं। हां, बस इतना है कि जब भावनाएं बेलगाम हो जाती हैं तो यह पागलपन कहलाता है। ये भावनाएं बाधा नहीं हैं। मैं जीवन को इस रूप में देखता हूं कि यहां क्या काम करता है और क्या नहीं। अगर आप लगातार नाराज हैं, कुंठित हैं, हताश हैं, नफरत से भरे हैं तो क्या ये भावनाएं आपके लिए काम करेंगी? नहीं। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को आनंद, दया और प्रेम से भरपूर बना लेते हैं तो ये आपके लिए जरूर काम करेंगी।

सद्गुरु

जन्म तारीख का गड़बड़झाला!

हमारा जमाना भी क्या जमाना था! बचपन में पांच साल तक घर में ही धमाचौकड़ी करो और फिर कहीं स्कूल की बात माता-पिता को याद आती थी। स्कूल भी सरकारी होते थे और बस घर में कोई भी जाकर प्रवेश करा देता था। हमारे साथ भी यही हुआ और हमारी उम्र के सभी लोगों के साथ कमोबेश यही हुआ है। पिताजी ने एक भाई को कह दिया कि इसका भी स्कूल में नाम लिखा दो, भाई की अंगुली पकड़कर हम चल दिए स्कूल। हेडमास्टर ने कहा कि फॉर्म भरो। फॉर्म में पूछा गया कि जन्म तारीख क्या है? अब भाई को कहां याद कि जन्म तारीख क्या है! पहले की तरह हैप्पी बर्थडे का रिवाज तो था नहीं, बस भाई को जो याद आया वह लिखा दिया। तारीख भी और वर्ष भी। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा! हमारी पढ़ाई शुरू हो गई, एक जन्म तारीख हमारी भी लिख दी गई, कागजों पर। लेकिन जब दसवीं कक्षा में पहुंचे तब पता लगा कि हम दसवीं की परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि उम्र कम है। पिताजी ने आनन-फानन में नए कागजात मय जन्मपत्री बनाई गई और अब हमारी जन्म तारीख बदल गई।

मां कहती कि तुम्हारा जन्म देव उठनी एकादशी को हुआ है और स्कूल कहता कि सितंबर में हुआ है। जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे थे, जन्मदिन मनाने की प्रथा भी बड़ी हो रही थी। हमें लगता कि हम तो मां ने जो बताया है उसे ही जन्मदिन मानेंगे, लेकिन स्कूल में जो दर्ज था लोग उसी दिन बधाई दे देते। इतना ही नहीं तिथि तो अपनी गति से आती और अंग्रेजी कैलेंडर से आगे-पीछे हो जाती। हमने फिर पंचांग का सहारा लिया और असली तारीख ढूंढ ही डाली। वास्तविक जन्मपत्री भी मिल गई तो तारीख पक्की हो गई। लेकिन कठिनाई यह है कि सरकारी कागजों में जन्म तारीख कुछ और है तथा हमारे मन में कुछ और! सरकारी कागजों की तारीख याद रहती भी नहीं, लेकिन कभी-कभी अचानक से कोई कह देता है कि जन्मदिन की बधाई! तो हम कुछ देर के लिए चौंक जाते हैं कि आज? आपके साथ भी होता ही होगा।

फिर से

जन्मदिन मनाते समय यह एहसास जन्म लेता है कि चलो एक दिन ही सही, कोई हमें विशेष होने का अवसर तो देता है

ऐसी ही एक बार अमेरिका के इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने हुआ। उसने आने का कारण पूछा, मैंने कहा कि बेटे से मिलने आई हूं। फिर वह बोला कि ओह आपका जन्मदिन आने वाला है, मैं एक बार तो चौंकी, लेकिन दूसरे क्षण ही मुझे ध्यान आ गया और उसकी हां में हां मिलाकर आ गई। मैं जब चाहे बधाई स्वीकार कर लेती हूं। कौन से जन्मदिन पर तीर मारने हैं! न तो हम अनोखे लाल हैं जो हमने धरती पर आकर किसी पर एहसान किया है और न ही हमारे जाने से धरती खाली हो जाएगी! लेकिन जन्मदिन मनाते समय एहसास जन्म लेता है कि चलो एक दिन ही सही, कोई हमें विशेष होने का अवसर तो देता है। नहीं तो हमारे आने की सूचना थाली बजाकर भी नहीं दी गई थी और न ही किन्नर आए थे नाचने। लेकिन मां बहुत खुश थी, पिताजी भी खुश थे। हम उन्हीं की खुशी लेकर बड़े होते रहे और अब अपने जमाने की रीत के कारण दो-तीन जन्मदिन मना लेते हैं। सोच लेते हैं कि क्या कुछ अच्छा कर पाए या यूं ही बोझ बढ़ाते रहे।

(अजित गुप्ता का कोना ब्लॉग से साभार)

मेलबाक्स

सिक्के का दूसरा पहलू

राजनीति की बदलती कार्य संस्कृति शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रदीप सिंह ने भाजपा की राजनीतिक शुचिता के रूप में सिक्के का केवल एक ही पक्ष उजागर किया है, जबकि इसका दूसरा स्याह पक्ष उस राजनीतिक विद्रूपता का है, जिसके बिना राजनीति को परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेखक ने राजनीति में सक्रिय बिना रसूख और पद प्रतिष्ठा वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को उचित स्थान देने की जो बात की है, वह अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस राजनीतिक विद्रूपता का जिक्र क्यों नहीं हुआ? जो राजनेताओं और उनके राजनीतिक दलालों को खाकपति से अरबपति बना देती है। इस देश की राजनीति का आखिर वह कौन सा फंडा है जिसका अनुसरण करके राजनीति में सक्रिय साधारण सा व्यक्ति राजनीतिक पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करते ही असाधारण सुख-संपत्ति का मालिक बन जाता है। अपवाद को छोड़कर हर राजनीतिक दल में ऐसे राजनेताओं की भरमार है जिनकी अपनी पैतृक संपत्ति लगभग शून्य थी, लेकिन सक्रिय राजनीति में आकर उन्होंने अपने वारिसों के लिए अकूत संपत्ति जरूर इकट्ठी कर दी है। राजनीति की यह विद्रूपता आज इसकी उस शुचिता को आच्छादित कर रही है, जिसका संदेश देने का प्रयास लेखक ने किया है। देश की राजनीति इस विद्रूपता से बाहर निकले इसके लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। चुनाव के समय प्रत्याशी अपनी चल-अचल संपत्ति की घोषणा तो करते हैं, लेकिन इनके स्रोत के खुलासे से बचते हैं। अपने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद जब वे दोबारा चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो उनकी सकल संपत्ति में हुई बढ़ोतरी के मामले में शायद ही कभी यह प्रश्न उठता हो कि पांच वर्षों तक पूर्णकालिक राजनीति करने वाला एक वेतनभोगी विधायक, सांसद और मंत्री किस समय कौन सा व्यापार कर लेता है कि उसकी आय में इतना अधिक इजाफा हो जाता है? निश्चित रूप से यह उसी राजनीतिक विद्रूपता का प्रतिफल है, जिसकी चर्चा से हर कोई बचना चाहता है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

परिंदों का ख्याल

पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पक्षियों की भूमिका हमेशा से ही अहम रही है। समाज में लोगों की धारणा ये भी है कि पक्षी गंदगी फैलाते हैं। इनके रहने से कोई लाभ नहीं है। इसी सोच के कारण इनकी संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। हम अपने रहने के लिए बड़े-बड़े घर, महल, कोठियां तो बनवा लेते हैं पर इन परिंदों के लिए एक कोना भी नही छोड़ते। एक दौर था जब लोग तोता पालना पसंद करते थे और उस तोते में कई खूबियां भी होती थीं। सुबह-सुबह राम-राम का जाप करता तोता लोगों को खूब भाता था। अब तोते इक्का-दुक्का ही नजर आते हैं। तोते के साथ गौरैया, बुलबुल, तितलियां आदि विलुप्त जीवों की श्रेणी में आ गए हैं। ये पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे के संकेत हैं। छप्पर के घर खत्म होने तथा पेड़ों की संख्या घटने से पक्षियों का आशियाना छिन रहा है। इसलिए पक्षियों को दाना-पानी देने की परंपरा को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं और घर बनाते समय पक्षियों का भी ध्यान रखें। घर में पेड़ जरूर लगाएं।

प्रशांत यादव, दिल्ली

नीतीश का बहाना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के घरों में पानी भरने के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि कई दूसरे शहरों में भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। अगर शहर में पानी भरने का कारण जलवायु परिवर्तन है तो राज्य के दूसरे शहर कैसे बचे हुए हैं? यह प्रशासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से शहर के सभी नाले बंद पड़े हैं। अगर नालों की समय से सफाई की गई होती तो यह समस्या इतनी विकराल नहीं होती।

श्रीनिवास यादव, गाजियाबाद

दिल्ली भी हो स्वच्छ

जयपुर रेलवे स्टेशन की तरह दिल्ली को भी सबसे स्वच्छ और सुंदर शहरों में शुमार होना चाहिए। कायदे में दिल्ली के रेलवे स्टेशनों को लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। यहां भी जयपुर की तरह अत्यधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और वे आगरा, शिमला, चंडीगढ़, शिमला जैसे स्थान घूमने के लिए ट्रेन का प्रयोग करते हैं। ऐसे में यह शर्मनाक बात है कि स्वच्छता के मामले में दिल्ली पहले 150 स्टेशनों में भी स्थान नही बना पाया है।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।